सैटेलाइट डेटा के अनुसार अगस्त में 33,116 बार ब्राज़ील के एमेज़ॉन जंगलों में आग लगी। गत 5 सालों में किसी भी महीने में इतनी ज्यादा आग की घटनाएं नहीं हुईं। एमेज़ॉन एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की साइन्टिफिक डायरैक्टर, एन एलेन्कार ने कहा कि, इस रिकॉर्ड तोड़ अग्निकांड की वजह, वनों की कटाई, ''ला नीना सायकल'' और अक्टूबर में ब्राज़ील में होने वाले चुनाव हो सकते हैं। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो अक्टूबर में पुनः चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, गत चार सालों में वनों की कटाई बढ़ी है जो बताती है कि, बोल्सोनारो प्रशासन का पर्यावरण एजेंडा क्या है, जिन्होंने वनों का संरक्षण करने वाली संस्थाओं को कमज़ोर किया है और अवैध कारगुज़ारियों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि, वृक्षों की ज्यादा कटाई का मतलब, आग लगने की घटनाएं बढ़ना है। बोल्सोनारो की सरकार पेड़ काटने वालों पर जरा भी सख्त नहीं है। किसान खेती के लिए जंगल जला देते हैं, पेड़ काट देते हैं और जिन पर पेड़ काटने के लिए जुर्माना लगाया जाता है वे जुर्माना नहीं भरते ना ही किसी को जेल होती है। इस वर्ष न्यूयॉर्क शहर से सात गुना बढ़े आकार का जंगल अगस्त से पहले तक काट दिया गया। उत्तरी अमेरिका के जंगलों के विपरीत, एमेज़ॉन के ह्यूमिड (आर्द्र) जंगलों में आग खुद ब खुद नहीं लगती, बल्कि लोग जानबूझ कर खेती के लिए और मवेशी का चारा उगाने के लिए आग लगाते हैं। एमेज़ॉन के वर्षावन महत्वपूर्ण ''कार्बन सिंक'' हैं, जो कार्बन डाई ऑक्साइड छोड़ते कम हैं और सोखते अधिक हैं। जंगल को जलाने पर यह कार्बन डाई ऑक्साइड वातावरण में मिल जाती है और ग्लोबल वॉर्मिंग को बढ़ाती है। इस बार आग लगने से 3.6 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साइड वातावरण में मिली है।

लद्दाख में विशाल और नया एयर फील्ड स्थापित करेगा हिन्दुस्तान

चीन की ओर से सीमा पर नये-नये युद्ध संबंधी निर्माणों के मद्देनज़र हिन्दुस्तान ने यह अहम् काउन्टर रणनीति तैयार की है

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। लद्दाख में चीन के खिलाफ भारत ने एक नई रणनीति तैयार की है। दरअसल हाल ही में कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि चीन पूर्वी लद्दाख से सटे इलाकों में भारी बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। अब चीन को काउंटर करने के लिए भारत जल्द ही न्योमा में एक नए हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू करने जा रहा है। न्योमा पूर्वी लद्दाख का बेहद अहम एरिया है।

भारतीय सेना के अधिकारियों ने को कहा कि भारत जल्द ही एल.ए.सी. से 50 किलोमीटर से कम दूरी पर लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए अपने न्योमा एडवांस्ड लैण्डिंग ग्राउंड के अपग्रेडेशन के लिए निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है। चीन के साथ चल रहे गतिरोध के दौरान न्योमा हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल जवानों और सामग्री के परिवहन के लिए किया गया है। इस हवाई क्षेत्र में चिनूक हेवी-लिफ्ट हेलिकॉप्टर और सी-130 जे स्पेशल ऑपरेशंस विमानों को भी उतारा जा चुका है। ''न्योमा एडवांस्ड लैण्डिंग ग्राउंड (एएलजी) को जल्द ही लड़ाकू विमान संचालन के लिए अपग्रेड किया जाएगा। अधिकांश आवश्यक मंजूरी और अप्रूवल पहले ही आ चुके हैं। योजना के अनुसार, नए हवाई क्षेत्र और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाएगा।'' एएलजी के अपग्रेडेशन से वायुसेना को बहुत ताकत मिलेगी। इस क्षेत्र से लड़ाकू विमानों के संचालन की क्षमता से वायु सेना की विरोधियों द्वारा किसी भी

- **भारत ने चीन सीमा से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर यह एयर फील्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है।**
- **सेना ने कहा है कि, लद्दाख में पहले से ही स्थापित ''न्योमा एयरफील्ड'' को बेहद उन्नत दर्जे पर अपग्रेड किया जायेगा। न्योमा पूर्वी लद्दाख का बेहद अहम् एरिया है। इस योजना के जरिये सीधे लद्दाख से हर प्रकार के लड़ाकू विमानों का संचालन किया जा सकेगा।**

दुस्साहस से तेजी से निपटने की क्षमता मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मोदी सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद पूर्वी लद्दाख सेक्टर में निर्माण कार्य का उद्घाटन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। भारत पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी (डी.बी.ओ.), फुकचे और न्योमा सहित कई हवाई क्षेत्रों के विकास पर विचार कर रहा है। यह इलाके चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) से कुछ ही मिनटों की दूरी पर हैं। न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) पर पहले ही वायुसेना के एम.आई.-17 हेलीकॉप्टर, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक हेवी-लिफ्ट हेलीकॉप्टर को उतारा जा चुता है व गरुड़ स्पेशल फोर्स ऑपरेशन का भी यहां संचालन किया गया है। हाल ही में, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अजय राठी ने न्योमा जैसे एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड के महत्व को समझाया था। राठी ने कहा, ''न्योमा एएलजी का वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब होने के कारण रणनीतिक महत्व है।

शर्मा की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिसकी योग्यता इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ ही पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन व डिस्ट्रिब्युशन में कार्य अनुभव है। राज्य सरकार ने मैंबर के खाली टैक्निकल पद पर बीएन शर्मा को 17 मई 2021 को नियुक्ति देते हुए कमीशन का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। जबकि राजस्थान पावर रिफॉर्म एक्ट 1999 और इलैक्ट्रिक एक्ट 1999 के अनुसार आयोग में टैक्निकल सदस्य पद पर इंजीनियरिंग सहित अन्य योग्यताधारक की नियुक्ति ही हो सकती है। इसलिए टैक्निकल मैंबर के पद पर बी.एन. शर्मा की नियुक्ति एक्ट 1999 के नियमों का उल्लंघन है। याचिका में अदालत से बी.एन. शर्मा को चेयनमैन पद पर काम करने से तुरंत रोकने और उनकी नियुक्ति को अवैध मानते हुए रद्द करने का आग्रह किया है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान और चीन में बड़ी हलचल

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर की धरती से ऐलान किया था कि, बहुत जल्द पी.ओ.के. को भारत में मिला दिया जायेगा

श्रीनगर, 27 अक्टूबर (वार्ता)। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को एक ऐसा बयान दिया है जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों में खलबली पैदा हो गई है, उन्होंने जम्मू-कश्मीर की धरती से एलान किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के बाद ही जम्मू- कश्मीर का भारत में विलय पूरा होगा।

जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय और वर्ष 1947 में जम्मू-कश्मीर को कबाइलियों के हमले से बचाने के लिए भारतीय सेना को वहां पहुंचाये जाने की याद में मनाये जाने वाले शौर्य दिवस के अवसर पर यहां आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षामंत्री ने कहा यह यात्रा तभी पूरी होगी जब हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ,अन्य हिस्सों के साथ गिलगित बाल्टिस्तान को भी वापस ले लेंगे। राज्य का विशेष दर्जा खत्म किये जाने के बाद यहां एक नई शुरूआत हुई है, यह तो बस शुरूआत भर है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब एक के बाद एक विकास के नये आयामों को छुऐंगे। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि हमने इन क्षेत्रों का विकास अभी शुरू ही किया है और अब हम उत्तरी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा, हमारी यात्रा तब पूरी होगी जब भारतीय संसद में 22 फरवरी 1949 को सर्वसम्मति से पारित किये गये प्रस्ताव को लागू कर देंगे और उसके हिसाब से बाकी बचे हिस्सों जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान के साथ दूसरे हिस्सों को भी अपनी ज़द में ले आयेंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा मैं पाकिस्तान से सवाल करना चाहता हूं कि उसने कश्मीर के जिस हिस्से पर

- **कश्मीर में शौर्य दिवस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि, 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में पारित किये गये प्रस्ताव को बहुत जल्द अमलीजामा पहनाया जायेगा और भारत जल्द ही गिलगित, बाल्टिस्तान सहित दूसरे हिस्सों को अपनी ज़द में ले लेगा।**
- **राजनाथ सिंह ने कहा कि, पाकिस्तान ने पी.ओ.के. के लोगों का जीवन अंधकारमय बना रखा है, वहां के लोगों को कोई भी मूलभूत अधिकार नहीं मिले हुये हैं तथा पाकिस्तान के राजनेता व सेना पी.ओ.के. के नागरिकों को लगातार यातनायें देते रहते हैं।**

अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ है वहां के लोगों को कितने अधिकार दिये हैं। पाकिस्तान जो मानवाधिकारों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहता है ,वह उसके कब्जे वाले इलाके के लोगों की कितनी चिंता करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीओके के लोगों के खिलाफ क्रूरता दिखाता है। सिंह ने कहा कि जम्मू -कश्मीर के देश का अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद यहां के लोग राजनीति के शिकार हैं। उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया है। एक ओर इस क्षेत्र की आजादी को धरती का स्वर्ग बताया जाता है तो दूसरी ओर इस भावना ने स्वार्थी राजनीति के सामने दम तोड़ दिया है।

उन्होंने कहा इस क्षेत्र को लंबे समय से अंधकार में रखा गया है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में विकास की नई बयार बही है। इससे पहले यहां हुई जबरदस्त हिंसा का शिकार अनगिनत जिंदगियां हुईं और अनगिनत घर बरबाद हुए। इसके कारण एक ही देश में दो विधान काम कर रहे थे। केंद्र सरकार की कितनी ही लाभकारी योजनाएं पंजाब की सीमा पार करके इस राज्य तक नहीं पहुंच पायीं।

75000नौकरियां ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्टंट मानकर इस पर संदेह व्यक्त करते हुए गोहिल ने पूछा कि ''क्या आपने इन लोगों को वास्तव में रोजगार दिया है? या आपने इन लोगों को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया है? और इन अभ्यर्थियों के चयन में किस प्रक्रिया का अनुसरण किया गया? इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, कृपया देश को बताएं कि इन नौकरियों का वितरण किस प्रकार किया गया और यह भी स्पष्ट करें कि ये पद कितने समय से रिक्त पड़े थे।'' ''आपने हर वर्ष दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। कई वर्षों बाद आय रोजगार मेला आयोजित करने का निर्णय लेते हैं। अब ऐसा छोटा रोजगार मेला क्यों, जबकि आपको 16 करोड़ नौकरियां पहले ही दे देनी चाहिए थीं? आपने प्रत्येक वर्ष दो करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दीं?कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पहले आरोप लगाया था कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पूर्व रोजगार मेले की नौटंकी करने के लिए करीब 75 हजार नियुक्ति पत्र कई महीनों तक रोक कर रखे गए और अभ्यर्थियों की भावना का कोई सम्मान नहीं किया गया।

''वंदे भारत'' ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ट्रेन सैट डिपो और वॉशिंग लाइन्स के साथ मैन पावर भी उपलब्ध करवाएगा, जो कि उसके तकनीकी साझेदार के ''सुपरविज़न और टैक्नीकल कंट्रोल'' में काम करेंगे।

रेलवे के स्टाफ के वेतन एवं भत्ते रेलवे ही देगा और सरकार नि:शुल्क पानी -बिजली के अलावा इलैक्ट्रिकल फिटिंग्स, केन्स, ट्रैक्स, ओ.एच.ई. सिस्टम्स के साथ बेसिक सिविल स्ट्रक्चर उपलब्ध करवाएगी। भारतीय रेलवे अपने टैक्नोलॉजी पार्टनर को ट्रेन सैट्स खरीदकर अनुगृहीत करेगा और उसे वार्षिक मेन्टिनैंस शुल्क भी दिया जाएगा जो कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का अनुमानत: 3.5 प्रतिशत होगा।

बिड दस्तावेजों की शर्तों को देखते हुए भारतीय रेलवे के कुछ अधिकारी कहते हैं कि वंदे भारत के कॉन्ट्रैक्ट्स देश के औद्योगिक विकास में अपना योगदान नहीं देंगे क्योंकि इनमें ट्रांसफर ऑफ टैक्नोलॉजी नहीं होगा। देश में रेलवे के कुल यात्री भार में एयर कण्डीशन्ड ट्रेन ट्रैवल का हिस्सा परम्परागत रूप से काफी कम रहा है। इस मामले में राजधानी और शताब्दी जैसी 50 विषम प्रीमियर ट्रेन्स पहले से ही पटरियों पर दौड़ रही है और आने वाले वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेन्स के और आ जाने से भारतीय रेलवे के अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं के साथ समझौता करने की उम्मीद है, क्योंकि इस पदानुक्रम में आगे गैर आरक्षित यात्री ट्रेनों की भरमार होने की संभावना है।

डॉनल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर खुले मंच पर भारत और हिन्दुत्व की पैरवी की

राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा, वे अगर 2024 में राष्ट्रपति बने तो भारत और अमेरिका के संबंधों को एक नये मंच पर ले जायेंगे

न्यूयॉर्क, 27 अक्टूबर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने कहा कि अगर वे 2024 में राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को अगले स्तर तक लेकर जाएंगे। फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो रिजॉर्ट में रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन (आर.एच.सी.) द्वारा आयोजित दिवाली कार्यक्रम में शामिल करीब 200 भारतीय-अमेरिकियों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके हिंदू समुदाय, भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि, अगर वे 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो आर.एच.सी. के संस्थापक शलभ कुमार को भारत में अपना राजदूत नामित करेंगे। आर.एच.सी. ने बीते दिनों दिवाली कार्यक्रम में ट्रंप द्वारा दिए गए भाषण का वीडियो को जारी किया। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि वह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, लेकिन अगर वह चुनाव लड़ते हैं और 2024 में जीत दर्ज करते हैं तो भारतीय-अमेरिकी समुदाय के प्रति उनकी कुछ खास प्रतिबद्धताएं होंगी। ट्रंप ने कहा, हमें 2016 और 2020, दोनों बार हिंदुओं का बहुत समर्थन मिला था और भारत तथा उसके लोगों का भी समर्थन मिला था। मैं वाशिंगटन डीसी में एक हिंदू होलोकास्ट स्मारक बनाने के विचार का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। उन्होंने वादा किया कि अगर वह 2024 में राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को अगले स्तर तक लेकर जाएंगे।

- **डॉनल्ड ट्रम्प ने दिवाली के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि, हिंदू समुदाय, भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं।**
- **ट्रम्प ने कहा, हमें 2016 और 2020, दोनों बार हिंदुओं का बहुत समर्थन मिला था और भारत तथा उनके लोगों का भी समर्थन मिला था।**

डॉ. स्वामी की सुरक्षा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमन्यम स्वामी, जिनसे सरकार उनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म होते ही सरकार बँगला खाली करने के लिये कह दिया था, गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय पहुँच गये। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है सरकार ने उन्हें यहाँ पश्चिम निजामुद्दीन क्षेत्र में स्थित उनके निजी निवास पर यथेष्ट सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई है। 14 सितम्बर को, उच्च न्यायालय ने उनसे कहा था कि वे छः सप्ताह के अंदर अपने सरकारी बँगले का स्वामित्व सरकार के ऐस्टेट कार्यालय को सँभलवा दें। उनके वकील ने गुरुवार को उच्च न्यायालय को बताया कि सरकार ने उनके निजी आवास पर कोई सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई है, जबकि सरकार ने उनको उस समय इसका आश्वासन दिया था, जब डॉ. स्वामी 26 अक्टूबर तक सरकारी बँगला खाली करने के लिये तैयार हो गये थे।

अदालत उनकी याचिका की आगे की सुनवाई सोमवार को करेगी। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुये डॉ. स्वामी, जो पूर्व केन्द्रीय मंत्री हैं, को 15 जनवरी, 2016 को कैबिनेट कमेटी ऑन ए कॉमोडेशन ने लुटियन्स जोन में पाँच साल के लिये सरकारी आवंटित कर दिया था। वे सितम्बर में सकरारी बँगले के पुर्नआवंटन के लिये उच्च न्यायालय गये थे। अदालत में उन्होंने ''सुरक्षा-संकट बने रहने'' का हवाला दिया था, लेकिन केन्द्र ने यह कहते हुये उनकी दलील का विरोध किया था कि अन्य मंत्रियों एवं सांसदों को आवास दिया जाना जरूरी है। पूर्ववर्ती सुनवाई में, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने निर्णय दिया था कि मूल आवंटन पाँच साल के लिये किया गया था।

- **भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, जिनको कार्यकाल पूरा होने पर सरकारी बंगला खाली करने का आदेश मिला है, ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कर अपने निजी आवास पर पर्याप्त सुरक्षा मांगी है।**

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किए जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। गत 26 फरवरी 2020 को जस्टिस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाई कोर्ट की दो जजों की एक बैंच ने दिल्ली दंगों से पूर्व भड़काऊ भाषण देने वालों के विरूद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई ना करने को लेकर केन्द्र सरकार की खिंचाई की थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस केन्द्र सरकार के ही अधीन है।

बैंच, पूर्व नौकरशाह हर्ष मंदर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा व अन्य पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था। जस्टिस मुरलीधर ने केन्द्र सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि वह इस अवधि में अपना यह रूख स्पष्ट करे कि क्या वह कथित भड़काऊ भाषणबाजों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने का इरादा रखती है या नहीं? लेकिन जब आगे के निर्देश पारित करते, उससे पहले ही 27 फरवरी 2020 को केन्द्र सरकार की एक अधिसूचना आ गई उनके व तीन अन्य जजों के तबादले की बात कही गई थी। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस अधिसूचना को जस्टिस मुरलीधर द्वारा एक दिन पूर्व दिए गए आदेश के परिणाम के रूप में देखा, तथापि तत्कालीन विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कोलीजियम द्वारा 12 फरवरी 2020 को की गई तबादले की सिफारिश का हवाला देकर विपक्ष पर मामले का अनावश्यक राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। लेकिन जहां तक जजों की नियुक्ति की मंजूरी में विलंब की बात है तो केन्द्र सरकार इस वर्ष की शुरूआत में यह साबित कर चुकी है कि यदि वह चाहे तो कोलीजियम की सिफारिशों को 48 घंटे के भीतर मंजूरी प्रदान कर सकती है।

दक्षिण भारत की यात्रा पर निकला... केरल में बर्ड फ्लू की दस्तक

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का एक व्यवसायी नन्द कुमार है। जब पुलिस का सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों से यह जानकारी मिली कि पैसे और बड़े पदों की पेशकश करके, उन्हें भाजपा में शामिल होने का प्रलोभन दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं, उसके बाद रवीन्द्र हैदराबाद से जुड़े हुये जिले रंगा रेड्डी के अजीज़ नगर कस्बे के संदर्भित फार्म हाउस में गया था। पुलिस ने बुधवार शाम को फार्म हाउस पर छापा मारा तथा तीन लोगों को हिरासत में ले लिया।

जब यह राजनैतिक घटना टेलीविजन के स्क्रीन तथा सोशल मीडिया तक पहुँच गई तो चार विधायकों- गुव्वाला बाला राजू (अचेम्पेट), रेगा कान्ता राव (पीनायाका), बीरम हर्षवर्धन रेड्डी (कोल्लापुर) तथा पंजूगुला रोहित रेड्डी (तन्दूर)- की तस्वीरें दो महात्माओं के साथ वायरल हो गई। प्रसंगवश बता दें कि इनमें से तीन विधायक पूर्व कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस के टिकट पर जीतने के बाद, टी.आर.एस. में शामिल हो गये थे। ये चारों विधायक सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय गये तथा बाद में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी।

टी.आर.एस. विधायकों ने मीडिया कर्मियों को बताया कि उन्होंने भाजपा के विधायक तोड़ने के अभियान को मात दे दी है। उन्होंने कहा, ''हमें पैसे से खरीदे जाने की साजिश को हमने उजागर कर दिया है।'' एक पार्टी विधायक ने कहा, ''हम के.सी.आर. के पैदल सैनिक हैं तथा हम पैसे के लालच में नहीं आयेंगे।''

जब यह समाचार मीडिया में पहुँच गया तो भाजपा ने तुरन्त इस कथित घटना से स्वयं को अलग कर लिया तथा कहा कि यह ''टी.आर.एस. का ''इन-हाउस ऑपरेशन'' था क्योंकि वह मुनुगोडे विधानसभा उपचुनाव की संभावित हार से डरी हुई थी तथा लोगों को ध्यान हटाने तथा भाजपा को बदनाम करना चाहती थी।''

केन्द्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने उल्टे आरोप लगाते हुये कहा है कि ''सभी पार्टियों से विधायक खरीदने का काम टी.आर.एस. ने किया था तथा भाजपा पर विधायक तोड़ने का झूठा आरोप लगाने का नाटक कर रही थी। ''टी.आर.एस. के चार विधायकों से पूछताछ तक भी क्यों नहीं की गई?''

रेड्डी ने माँग की कि इस मामले की गहन जाँच सी.बी.आई. से कराई जाये तथा स्वयं मुख्यमंत्री की भूमिका की भी छानबीन की जायें क्योंकि ''हॉर्स ट्रेडिंग'' उनका इतिहास रहा है। रेड्डी ने यह भी जानना चाहा कि इस बात का क्या प्रमाण है कि आरोपी भाजपा से जुड़े हुये हैं। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि पुलिस ने सी.सी.टी.वी. फुटेज क्यों नहीं जारी की। रेड्डी ने इस बात से दृढ़तापूर्वक इंकार किया कि भाजपा का कोई व्यक्ति न तो फार्म हाउस पर मौजूद था और न पार्टी इस गलत काम से जुड़ी

- **भाजपा ने यह भी सवाल उठाया कि, पुलिस ने अभी तक चारों विधायकों से गहरी पूछताछ क्यों नहीं की और इस बात का क्या सबूत है कि, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का भाजपा से कुछ भी संबंध है।**
- **भाजपा का यह भी आरोप है कि, तेलंगाना राष्ट्र समिति मनु गोडे का एसेम्बली का उपचुनाव हारने जा रही है, इसलिये भाजपा द्वारा विधायक खरीद का यह नाटक रचा है। तेलंगाना में आरोप-प्रत्यारोप के कारण राजनीतिक स्थिति धूमिल सी है, पर कर्नाटक में, जो दक्षिण भारत में भाजपा का सबसे प्रमुख राज्य है और जहां भाजपा की सरकार भी है, में जरूर भाजपा की स्थिति स्पष्ट रूप से कमजोर हुई है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के पुनर्जिवित होने से। कांग्रेस नेता भी आक्रामक शैली से इस पुनर्जिवित होने की हवा का पूरा लाभ लेने की तैयारी में हैं।**

उन्होंने पुलिस पर इतने घटिया स्तर तक उतर आने का आरोप लगाया तथा कहा कि पुलिस अधिकारियों तथा के.सी.आर. सरकार की मिली भगत है तथा पुलिस मुख्यमंत्री द्वारा तैयार कथानक के अनुरुप कार्य कर रही है। रेड्डी ने सवाल खड़ा किया, फलस्वरूप, आम जनता की नजर में, टी.आर.एस. द्वारा लगाये जा रहे आरोप विश्वसनीय प्रतीत हो रहे हैं- भले ही इस प्रकरण की सच्चाई कुछ भी हो। तेलंगाना की ताजातरीन इस विधायक चोरी (पोचिंग) में भाजपा शामिल न भी हो तो भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड लोगों की नजरें उनके इंकार को संदेहास्पद श्रेणी में ही रख रही हैं। आम जनता तमिलनाडु तथा केरल में भी भाजपा के कृत्यों को बड़ी सजगता एवं सतर्कता के साथ देख रही है। ज्ञातव्य है कि जनता इस समय तथा पूर्ववर्ती चुनावों में भी, भाजपा के पक्ष में नहीं रही है। केरल के राज्यपाल द्वारा राज्य के वित्त मंत्री को उनके पद पर बने रहने की अपनी प्रसन्नता को वापस लिया जाना, अर्थात उन्हें बर्खास्त करने की कोशिश करना केरल की जनता की नजर में एक नकारात्मक कदम ही रहा है।

ज्ञातव्य है कि केरल साक्षरता के मामले में देश में सबसे ऊपर है। दक्षिण भारत, जहाँ से लोकसभा के 130 सांसद आते हैं, जो कुछ भी भाजपा के पास है, उसे खोती नजर आ रही है। पिछे आम चुनावों में, भाजपा ने कर्नाटक में इकतरफा जीत हासिल की थी, लेकिन तेलंगाना, जहाँ से उसे चार सीटें मिली थीं, के अलावा अन्य किसी दक्षिण भारतीय राज्य में प्रवेश भी नहीं कर पाई थी और भाजपा यहाँ अपनी जमीन तैयार करने तथा अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की आशा लगाये बैठी है तथा अन्य पार्टियों, खासतौर से कांग्रेस के राजनेताओं को तलाशने एवं चुराने की कोशिश कर रही है।

दो तेलुगू भाषी राज्यों- आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में उनकी चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने के लिये भाजपा नेतृत्व फिल्म स्टारों तथा अन्य सेलिब्रिटीज को अपने साथ लाने एवं चुनावों में उतारने की भी कोशिश कर रही है।

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (वार्ता)। केंद्र सरकार ने केरल में एवियन इनफ्लुएंजा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए एक उच्च स्तरीय दल भेजा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को यहां बताया कि केरल में एवियन इन्फ्लुएंजा

- **केंद्र सरकार ने केरल में एवियन इनफ्लुएंज़ा यानी बर्ड फ्लू की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए एक उच्च स्तरीय दल जांच एवं बेहतर इंतजामात के लिए वहां भेजा है।**

के प्रकोप की जांच के लिए उच्च स्तरीय दल भेजा है। यह दल एवियन नफ्लुएंजा प्रकोप का विस्तार से जांच करेगा और सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा।

केरल के लिए सात सदस्यीय केंद्रीय दल में राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नई दिल्ली, राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान, चेन्नई और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के विशेषज्ञ शामिल हैं। जांच दल का नेतृत्व क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय, बैंगलोर के डॉ राजेश केदामणि कर रहे हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908